Regulator on 100 day agenda

*332.DR. T. SUBBARAMI REDDY:

MS. MABEL REBELLO:†

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Ministry has decided to put appointment of a regulator on 100 day agenda;

(b) if so, whether the Minister has asked the State Governments to expedite the process of coal production in several captive blocks that have been lying idle due to delay in obtaining clearance;

(c) whether Government has allocated 196 coal mines, with estimated reserves of 40 billion tonnes, of which only 13 have become operational, so far;

(d) whether the Ministry has decided not to increase the prices but emphasis is on raising the production; and

(e) if so, the outcome of discussions held with States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Ministry of Coal has not decided to put appointment of regulator on 100 day agenda, as this would require enactment of statute by the Parliament.

(b) and (c) During the review meetings, the State Governments concerned were requested to expedite the process of land acquisition and other statutory clearances. 201 coal blocks with geological reserves of about 45 BT have been allocated (upto May, 2009) to various public and private companies for different end uses specified in Section 3(3)(a) of the Coal Mines (Nationalization) Act, 1973. So far production has commenced in 25 coal blocks and the production from these coal blocks for the year 2008-09 (upto March, 2009-Provisional) was 30.02 million tonnes.

(d) and (e) Pricing of coal has been decontrolled since 01.01.2000. The coal companies themselves fix the coal price based on input costs, inflation index, market trends etc. and notify the same periodically. Coal production is envisaged to be raised from 454.42 million tonnes at the end of the X Plan (2007-08) to 731 million tonnes by the end of the XI Plan (2011-12). During the recent visit of Minister of State (Independent Charge) for Coal to some of the coal producing States, the State Governments were requested to facilitate expeditious processing of land acquisition, resettlement and rehabilitation, other statutory clearances etc. in respect of coal projects in order to increase production of coal. They have agreed to extend their support and assistance in this regard.

MS. MABEL REBELLO: Sir, the hon. Minister in his reply has said that 201 coal blocks up to May, 2009, have been allotted and only 25 coal blocks have started production. This shows that hardly 12 per cent of coal blocks have started production. The hon. Minister also says that he went to the States and discussed the issue. I would like to know what the progress is; and, how he has managed to get the companies, who have been allotted coal blocks. How has he motivated them to start production in the cancelled blocks, allotted to them?

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Ms. Mabel Rebello

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन की 55% आवश्यकता कोल के द्वारा ही पूरी की जाती है। कोल के प्रोडक्शन और कोल की आवश्यकताओं के गैप को देखते हुए भारत सरकार ने कोल ब्लॉक्स को एलॉट करने की एक प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत लगभग 201 कोल ब्लॉक्स एलॉट किए गए। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्या ने यह चिंता जाहिर की है कि लगभग 25 कोल ब्लॉक्स ही अभी तक इफैक्टिव हुए हैं और जिनमें ऑपरेशन शुरू हुआ है। बाकी कोल ब्लॉक्स में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। जब हमने बारीकी के साथ इसका अध्ययन किया तो इसमें सबसे बड़े दो हर्डल्स सामने आए। एक हर्डल लैंड एक्विज़िशन का है और दूसरा पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लैवल पर भी होता है और सैंट्रल गवर्नमेंट के लैवल पर भी होता है। इस संबंध में हमने पर्यावरण मंत्री जी से बात की और मुझे खुशी है कि तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच साल से लटके हुए मामलों में हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हर कीमत पर हम पर्यावरण की क्लीयरेंस छः महीने के अंदर-अंदर दे देंगे। पिछले दो महीने के अंदर हमने जिन-जिन राज्यों में दौरा किया है, इस दौरान मैं पश्चिमी बंगाल गया, झारखंड भी गया तब वहां के मुख्य मंत्री और वहां के गवर्नर से हमने बात की ...(**व्यवधान**)...

सुश्री मैबल रिबैलो : वहां मुख्य मंत्री हैं ही नहीं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैंने कहा कि वहां के मुख्य मंत्री और वहां के गवर्नर से हमने बात की। मैंने सही रिप्लाई किया है। उनसे हमने कहा कि पर्यावरण के संबंध में आप जल्दी क्लीयरेंस देने की प्रक्रिया शुरू करिए। अगर तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच साल तक पर्यावरण की क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी, तो जिस मकसद से हमने कोल ब्लॉक्स ऐलॉट किए हैं, हमारा वह मक़सद पूरा नहीं होगा। इसी तरीके से हमने स्टेट गवर्नमेंट्स से यह बात भी की कि लैंड एक्विज़िशन की कार्यवाही को पूरे तरीके से अंजाम देने का कार्य स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हमें दोनों राज्यों से इस चीज़ का आश्वासन मिला है। जहां-जहां और कोल माइनिंग होती है, पार्लियामेंट के सैशन के बाद मैं उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स से भी मिलूंगा और उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण क्लीयरेंस और लैंड ऐक्विज़िशन की कार्यवाही को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि हमने जो ब्लॉक्स ऐलॉट किए हैं, उनका उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके और डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है, उसे हम पूरा कर सकें।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Prasanta Chatterjee.

MS. MABEL REBELLO: My second supplementary, Sir?

MR. CHAIRMAN: You are only associated with the question. You did not ask it. ...*(Interruptions)*... I am afraid, if the main questioner is absent that right cannot be delegated to someone else. ...*(Interruptions)*... No.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, illegal mining in the abandoned coalmines is rampant in Jharkhand and at many other places. There is a great nexus between the coal mafia and others. And, this problem is very much linked to the number of accidents that take place there and the resultant loss of lives, apart from other issues. So, my question is this. How does the Government take care of this serious problem? Who will provide funds for filling up of abandoned colamines? It is very necessary to fill up the abandoned coalmines.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, हमारी कोल कंपनीज़ के द्वारा एबान्डंड कोल माइन्स को फिल करने की प्रक्रिया बराबर की जाती है और उनकी फिलिंग कर दी जाती है, लेकिन जैसा हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है, उनकी जिज्ञासा है और यह बात सही भी है कि हमारे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में इल्लीगल कोल माइनिंग तेजी के साथ जारी है। हमने मुख्य मंत्री जी के साथ और गवर्नर साहब के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें भी इस बिंदु को उठाया था कि जब तक इल्लीगल माइनिंग नहीं रुकेगी, तब तक उचित कदम नहीं उठाए जा सकते हैं और कोल का प्रोडक्शन वास्तव में नहीं बढ़ सकता है। हमें वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और झारखंड के गवर्नर साहब ने यह आश्वस्त किया था कि हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। झारखंड के गवर्नर साहब ने यह कहा था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स ...(**व्यवधान**)... मैंने झारखंड का गवर्नर कहा। झारखंड के गवर्नर और पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर कहा।

सर, हमें झारखंड के गवर्नर साहब ने यह आश्वस्त किया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स की तर्ज पर हम स्टेट की इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स भी बना रहे हैं और वह करीब-करीब ट्रेंड होकर तैयार हो गई है, हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए उस फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने हमसे यह भी कहा कि आपको अगर आवश्यकता हो तो आप सी.आई.एस.एफ. की तर्ज पर हमारी स्टेट की सेक्योरिटी फोर्स भी हमसे लीजिए और इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जो भी प्रभावकारी कदम आप उठाएंगे, उसमें हम आपको पूरा सहयोग देंगे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर हमारी माइनिंग हो रही है, वहां की सुरक्षा करना तो हमारी सी.आई.एस.एफ. का दायित्व है, जिसके लिए हमने सी.आई.एस.एफ. को सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रखा है, लेकिन कोल फील्ड्स बहुत लम्बी-चौड़ी है। कानून-व्यवस्था और पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ...(**व्यवधान**)... मैडम, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हम अभी इल्लिगल माइनिंग की बात कर रहे हैं। कोल फील्ड्स बहुत बड़ी होती है। जहां माइनिंग हो रही है वहां तो है ही, इसके अलावा उससे दस गुनी ज्यादा कोल फील्ड्स होती है, जहां पर कोल उपलब्ध होता है। इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग केन्द्र सरकार को नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इल्लिगल माइनिंग को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। ...(**व्यवधान**)... येचुरी जी, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमारे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने बहुत ही कोऑपरेटिव रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारियों को यह निर्देश करेंगे कि सी.आई.एस.एफ. के साथ पूरे तरीके से तालमेल रखें, कोल कम्पनीज़ के साथ पूरे तरीके से तालमेल रखें और इल्लिगल माइनिंग को रोकने के लिए जो भी कड़े-से-कड़े कदम उठाए जा सकें, वे उठाए जाएं। आपको ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... Please, we are running out of time. Don't interrupt.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : फिलिंग की जहां तक बात है, तो जैसे ही माइनिंग का काम खत्म होता है वैसे ही वहां पर फिलिंग कर दी जाती है। लेकिन, फिलिंग किए गए क्षेत्रों में अगर इल्लिगल माइनिंग करने वाले फिर से इल्लिगल माइनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वह एक प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ी होती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही हम स्टेट्स का दौरा कर रहे हैं और हम आपको, माननीय सदस्य को, आश्वस्त करते हैं, कि हरेक क्वार्टरली हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और मिल कर उनसे इस मामले में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम थेफ्ट भी रोकने में कामयाब होंगे और इल्लिगल माइनिंग पर भी कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ परसेंट अंकुश लगाने में जरूर कामयाब होंगे।

श्री नतुजी हालाजी ठाकोर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार को जो कोयला दिया जा रहा है वह पूर्वी क्षेत्र से दिया जा रहा है। वह दूरी 16 सौ किलोमीटर की है। उसके हिसाब से परिवहन-क्षेत्र का जो खर्च है, वह बढ़ जाता है। गुजरात सरकार की बार-बार रजुआत के बावजूद भी हमें पश्चिमी क्षेत्रों से कोयला नहीं दिया जा रहा है। इसके क्या कारण हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, गुजरात सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, जिस कोल कम्पनी से जिसको कोयला अलॉट हुआ है, उन कोल कम्पनीज़ से उस स्टेट को कोयला जा रहा है। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है। गुजरात में बहुत-से लोग कोल का इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। आपने जिस मामले में हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उस संबंध में हमें गुजरात सरकार का भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। हम यह देख रहे हैं कि जिन कम्पनीज़ से गुजरात गवर्नमेंट कोयला मांग रही है, क्या उनके पास इतना कोयला है कि वह गुजरात सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? अगर ऐसा होगा तो हम उनकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे।

श्री आर.सी. सिंह : सर, जिन कम्पनीज़ को आउटसोर्सिंग करने के लिए सरकार अधिकार दे रही है, वे क्या माइनिंग रूल्स, रेगुलेशंस और वर्कमैन का जो वेज़-एग्रीमेंट होता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, जिनको भी आउटसोर्सिंग की अनुमति दी जाती है, उनको सरकार अपनी शर्त पर, अपने कानून पर और अपने विधान की शर्तों पर ही आउटसोर्सिंग की अनुमति दे सकती है। अगर वे सरकार के किसी भी कानून का वॉयलेशन करती हुई पाई जाएंगी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री आर.सी. सिंह : सर, बैक फिलिंग एक ही कम्पनी नहीं कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Schemes of the Ministry of New and Renewable Energy

*324.SHRI SABIR ALI: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) the details of programmes and schemes of the Ministry;

(b) in what manner these are being popularized;

(c) the targets for the current financial year; and

(d) in what manner the intended targets are being achieved in Uttar Pradesh and Bihar?

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): (a) Details of the major schemes / programmes supported by the Ministry of New and Renewable Energy are given in the Statement-I (*See* below).

(b) The Government has taken several steps and measures to popularize and encourage renewable energy schemes / programmes in the country which include the following: